

अपने दायित्व का निर्वाह बड़ी ही ईमानदारी से करते हैं। परन्तु, इन्हें अभी तक सरकार द्वारा एक्सट्रा डिपार्टमेंटल कर्मी के रूप में ही माना जाता है, जिसके कारण इन्हें स्थायी कर्मी की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। महिला कर्मियों के सामने तो दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर प्रसूती के समय छुट्टी की व्यवस्था न होने से बच्चे जनने में उन्हें असुविधा होती है। इन सारी असुविधाओं से स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों के बीच बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है। अस्थायी कर्मचारियों में रोष का कारण आंदोलन का सिलसिला पूरे देश में चल रहा है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि भारतीय डाक विभाग के 1,90,000 अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने का कष्ट करे, ताकि इन्हें स्थायी कर्मी की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।

**श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश):** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

**श्री रुद्रनारायण पाणि (ओडिशा):** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

**श्री तरुण विजय (उत्तराखंड):** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

**श्रीमती स्मृति जुविन ईरानी (गुजरात):** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

**श्री अम्बेथ राजन (उत्तर प्रदेश):** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

**श्री वृजलाल खावरी (उत्तर प्रदेश):** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

**श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश):** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

**श्री प्रमोद कुरील (उत्तर प्रदेश):** महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

#### **Demand to take steps for development of National Highways in Odisha**

SHRI RUDRA NARAYAN PANY (Odisha): Sir, there are sixteen national highways measuring 3,594.162 kms. in length traversed through the State of Odisha. Out of which, 2,523.963 kms. is under the control of National Highways Wing of the State and the remaining 1,070.299 kms. have been entrusted to the National Highway Authority of India for improvement under the Golden Quadrilateral, Port Connectivity and the National Highway Development Programme Phase-III. During NDA period, a good number of roads were declared as national highways by Dr. Devendra Pradhan, the then Minister of State for Surface Transport. After that, 399 kms. of State roads were declared as new national highways during 2004. Since then no State road has been considered for

declaring as national highway. It is learnt that the Government of India has declared State roads as new national highways in other States during the last seven years. I, therefore, hereby demand for declaration of the following roads as new national highways:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Berhampur-Koraput     | 313 kms.   |
| 2. Madhapur-Rayagada     | 292.6 kms. |
| 3. Phulanakhara-Konarka  | 104 kms.   |
| 4. Kuakhia-Aradi-Bhadrak | 96 kms.    |

Sir, the following stretches of national highways in Odisha have been entrusted with the National Highway Authority of India for upgradation to four-lane:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. Luhurachati to Sambalpur | 88 kms.  |
| 2. Bhubaneswar to Puri      | 59 kms.  |
| 3. Talcher to Chandikhol    | 134 kms. |
| 4. Panikoli to Remuli       | 163 kms. |
| 5. Remuli to Rajamunda      | 106 kms. |

I, hereby, demand for speedy action and completion of these projects.

Sir, the other points to which I wanted to draw the attention of the hon. Minister are:

The high level bridge existing on Mumbai-Kolkata highway near Bargarh in my State across the river Jeera has been damaged severely. Its repair work should be completed on a war-footing.

Talcher-Gopalpur via Hindoli shall be declared as national highway. Thank you.

SHRI PRAMOD KUREEL (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri Pany. Thank you.

**Need for guidance to the Government of Bihar in  
connection with MPLAD Scheme**

**श्री राजनीति प्रसाद (बिहार):** महोदय, हाल ही में बिहार सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को लागू करने के बारे में दिशा-निर्देश दिए हैं। जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, यदि उनका अध्ययन किया जाए, तो यह प्रतीत होता है कि बिहार में सांसद निधि के तहत संस्तुत योजनाएं जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया के संजाल में